provisions of the Constitution of the State of Jammu and Kashmir.

It is Government of India's concern that in the sensitive border State of Jammu and Kashmir, peace and good order prevails and the nefarious designs and activities of those who are seeking to undermine the integrity and unity of India are effectively checked. I would therefore, appeal to the Honourable Members to view the recent developments in the State of Jammu and Kashmir in the right perspective and strengthen the hands of the Government.

[1] MR. DEPUTY SPEAKER : The House stands anjourned to meet at 1425 hrs. after lunch.

13·22 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till twenty five minutes past fourteen of the clock.

———

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at twenty-nine minutes past Fourteen of the Clock

[MR. DEPUTY SPEAKER IN THE *in the Chair*]

ELECTION TO COMMITTEE

Recommendation to Rajya Sabha to nominate a Member to Committee on Public undertakings

SHRI KAMALUDDIN AHMED (Warangal) : I beg to move :

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate a member from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings of this House for the unexpired portion of the term of the committee in the vacancy caused by the resignation of Miss Saroj Khaparade from the Committee and do communicate to this House the name of the member so nominated by Rajya Sabha."

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate a member from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings of this House for the unexpired portion of the term of the committee in the vacancy caused by the resignation of Miss Saroj Khaparade from the Committee and do communicate to this House the name of the member so nominated by Rajya Sabha."

The motion was adopted

———

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need for early completion of Ghosi-Khurd Irrigation Project

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के भंडारा जिले की घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना पर विचार अब से 10-12 वर्ष पूर्व शुरु हुआ था और उस समय इस पर अनुमानित लागत 160 करोड़ रुपये थी किन्तु कुछ अधिकारियों की ढील के कारण और कुछ इस महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना को प्राधान्य न देने के कारण अभी तक कार्यान्वित नहीं हो सकी है और इसका लागत व्यय भी बढ़कर 438 करोड़ रुपये हो गया है। इस योजना से लगभग 5 लाख एकड़ भूमि सिंचित करने का लक्ष्य है और

(श्री विलास मुत्तेमवार)

मात्र इस योजना से महाराष्ट्र कम से कम चावल के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेगा।

इसी प्रकार की ह्यूमन रिवर प्रोजेक्ट तथा तुलतुली इर्रीगेशन प्रोजेक्ट हैं, जिन पर मात्र 37 करोड़ रुपये और 29 करोड़ रुपये व्यय होंगे किन्तु यह भी कागजी विचार चलने के कारण 4 वर्ष से लटक रही है।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह प्रधानमंत्रीजी की भावनाओं का आदर करते हुए और उनके 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना को तत्काल कार्यान्वित करायें ताकि देश को खाद्यान्न किसी भी हालत में आयात न करना पड़े वरन् हम निर्यात की ओर अग्रसर हो सकें।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर इस योजना को युद्ध स्तर पर पूरा करायें।

(ii) Need for protection of Bhakra Canal and financial assistance to the farmers afflicted by breach in canal.

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, नहर भाखड़ा जो राष्ट्र की सम्पत्ति है और इस पर जो खर्चा लगा है, वह समूचे राष्ट्र का है। यह बात दूसरी है कि खुश हैसियती टैक्स किसानों से हरियाणा, पंजाब व राजस्थान में वसूला गया लेकिन यह समूचे राष्ट्र की सम्पत्ति है। इसको अगर कोई आघात पहुंचता है तो राष्ट्र के कलेजे पर चोट लगती है। पंजाब में आतंकवाद की आग से जब भारत की फौज जूझ रही थी, तब देश-द्रोहियों ने इस नहर को काटा और हरियाणा, पंजाब व राजस्थान को ने सिर्फ फसल से ही वंचित रखा बल्कि बच्चे, बूढ़े और पशु प्यास से व्याकुल रहे। बीमारी और मौत भी हुई। मरम्मत करवायी गयी। करोड़ों रुपये लगे। देशद्रोहियों ने फिर काट दी। अब फिर मरम्मत हो रही है। परन्तु देशद्रोही धमकी दे रहे हैं कि जो नहर की मरम्मत करेंगे, उन इन्जीनियरों को गोली से मार दिया जाये। यह देश को खुली चुनौती है। इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

जो पोस्टर छपे हैं, उनकी जांच हो तथा उन पर देशद्रोहियों को मुकदमा दर्ज किया जाये और उनकी प्रेस को जब्त किया जाये यथा उन देशद्रोहियों को सख्त सजा दी जाये। नहर की रक्षा राष्ट्रीय स्तर पर की जाये।

जो नुकसान हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के किसानों को हुआ है, सरकार राष्ट्रीय कोष से उसे दे। हर किस्म की वसूली व कर्जा राज्य सरकारें माफ करें और केन्द्र सरकार उनका भुगतान करे। जो फसल अब बोई जानी है, उसके लिये दूसरे दरियाओं से हरियाणा को पानी दिया जाये।

(iii) Need to streamline the management of various Schools in Tamil Nadu afficiated to Central Board of Secondary Education.

DR. A. KALANIDHI (Madras Central); The schools affiliated to the Central Board of Secondary Education are a separate category in the sense that neither the Central nor the State Government has any control over them. There is mushroom growth of these schools in Tamil Nadu. There are no fixed pay-scales for the staff